भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4587

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2025

असम के शोणितपुर जिले में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

4587. श्री रंजीत दत्ता:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम के शोणितपुर जिले में जनजातीय लोगों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए वहां एक नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार असम के शोणितपुर जिले में जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) 2018-19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस की स्थापना की जाएगी।

असम के शोणितपुर जिले में ऐसा कोई ईएमआरएस अनुमोदित नहीं किया गया है, क्योंकि उपर्युक्त दोहरे मानदंडों के अनुसार शोणितपुर जिले में कोई भी ब्लॉक ईएमआरएस की स्थापना के लिए पात्र नहीं है।

(ख) और (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए):

ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा ग्यारह और उससे ऊपर के लिए):

iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (पहले इसे शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जाना जाता था): प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में 265 शीर्ष श्रेणी के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

iv. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: भारत में एम. फिल या पीएचडी करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं खुली (ओपन एंडेड) हैं और 2.5 लाख रुपये तक की आय वाले प्रत्येक अजजा छात्र इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) में शिक्षा क्षेत्र सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में गंभीर अंतरों की संतृप्ति की परिकल्पना की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत इन विद्यालयों के उन्नयन और नवीनीकरण (जीर्णोद्धार) का प्रावधान है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए 100% अनुदान के साथ लगभग 7500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। डीएजेजीयूए के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने जनजातीय बच्चों की शिक्षा तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए 1000 छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने असम में 87 छात्रावासों सहित 304 छात्रावासों को स्वीकृति दी है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (जनमन) के अंतर्गत, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए 500 छात्रावासों के निर्माण में सहायता कर रहा है, जिनमें से 194 को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) भी समग्र शिक्षा अभियान को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतरों को पाटना है। यह योजना अजा, अजजा और अल्पसंख्यक समुदायों की सघनता के साथ-साथ नामांकन, प्रतिधारण और लैंगिक समानता के विभिन्न संकेतकों पर प्रतिकूल प्रदर्शन के आधार पर पहचाने गए विशेष ध्यान दिए जाने वाले जिलों (एसएफडी) पर भी ध्यान केंद्रित करती है। कुल 109 अजजा एसएफडी की पहचान की गई है, जिनकी आबादी अजजा आबादी की 25% या उससे अधिक है। समग्र शिक्षा के प्रमुख उपायों में आरटीई पात्रता शामिल है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक सभी बालिकाओं और अजा/अजजा/बीपीएल परिवारों से संबंधित बच्चों के लिए दो सेट यूनिफॉर्म प्रदान की जाती हैं और सरकारी/स्थानीय निकाय एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अजा/अजजा सहित सभी बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान भी किया जाता है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित बालिकाओं (कक्षा VI से XII) के लिए आवासीय विद्यालय हैं।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के अंतर्गत शोणितपुर में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) है।

****